आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 04.03.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, धार्मिक क्षेत्रों के पास स्थित शराब बिक्री की अनुमति को रद्द किया जाएगा।
- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्कूलों में स्थानीय अनाज को मिड डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में वित्तीय जागरूकता पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत बढ़ी।
- बागेश्वर जिले में मेलाडुंगरी हेलीपेड पर हेलीसेवा का सफल ट्रायल संपन्न।

नई आबकारी नीति

राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी देते हुए धार्मिक क्षेत्रों के पास स्थित शराब बिक्री की अनुमति को रद्द करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी देते हुए धार्मिक क्षेत्रों के पास स्थित शराब अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर कड़े नियंत्रण के साथ उप–दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। देहरादून में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि किसी दुकान पर एम०आर०पी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एम०आर०पी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी।

नई नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी और थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड के निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे स्थानीय किसानों और बागवानी क्षेत्र को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही, मदिरा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती की गई है, और माल्ट और स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। नई नीति को आर्थिक मजबूती, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर सृजित होंगे।

ईट राइट मूवमेंट

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के स्कूलों में ईट राइट मूवमेंट के तहत स्थानीय अनाज जैसे मंडुआ और झंगोरा को मिड डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिये सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स की खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि शुरूआती चरण में प्रदेश में छह मॉडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएंगे। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) की समीक्षा की। इस दौरान देहरादून के एक सहायता प्राप्त विद्यालय, हरिद्वार के छह मदरसों और ऊधमसिंह नगर के दो मदरसों को पीएम पोषण योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया। इसके तहत छात्रों के लिए प्रत्येक सप्ताह एक स्वास्थ्य कक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ निजी डॉक्टर, मेडिकल इंटर्न, पेरामेडिकल स्टाफ और आयुष चिकित्सकों की मदद ली जाएगी। साथ ही पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाएगा।

रीप कार्यशाला

अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रीप) की दो दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 11 विकासखंडों से 18 कार्मिकों ने भाग लिया।

कार्यशाला में पशुपालन, कृषि, मशरूम, मसाला उत्पादन और मार्केटिंग जैसी आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सहकारिता संगठनों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। जिला सहायक प्रबंधक संदीप सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण स्टाफ को क्रियाशील और कौशल विकास में सहायक होगा।

कार्यशाला के पहले दिन कल पिंक ई–रिक्शा योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

नीति आयोग

महिलाओं में वित्तीय जागरुकता पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत बढ़ी है। यह बात आज नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट बॉरोअर्स टू बिल्डर्स– वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी में कही गई है।

बैठक

सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने देहरादून स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं को गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया और संबंधित विभागों को सड़कों की जल निकासी व्यवस्था सुधारने और गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद ने कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराने और उनकी देखरेख सुनिश्चित करने पर बल दिया। मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए बकाया भुगतान जल्द करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और अन्य केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

ट्रायल संपन्न

बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में मेलाडुंगरी हेलीपेड पर हेलीसेवा का सफल ट्रायल संपन्न हुआ। अधिकारियों का कहना है कि सफल ट्रायल के बाद अब देहरादून और हल्द्वानी के लिए नियमित उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी। हेलीसेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय लोगों ने शासन–प्रशासन का आभार जताया है। गरुड़ के उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि नागरिक विमानन महानिदेशालय की अंतिम स्वीकृति के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू होगी।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

उत्तराखंड में सोमवार को हुई धामी कैबिनेट बैठक की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से लिखा है. ..हिन्दुस्तान समाचार पत्र पहले पृष्ठ पर लिखता है– उत्तराखंड में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, प्रमोशन में मिलेगा शिथिलता का लाभ। अमर उजाला लिखता है– 17 प्रस्तावों पर हुई चर्चा।

उत्तराखंड में राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे छात्र– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– छठी से 8वीं तक बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत व विभूतियां पुस्तक।

उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को बेहतर हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक हुई...जिस पर दैनिक जागरण सांसद त्रिवेंद्र सिंह के हवाले से लिखता है– एयरपोर्ट को चारधाम यात्रा से जोड़ने को तैयार करें योजना।

चमोली जिले के माणा में हुए हिमस्खलन हादसे की अब जांच होगी... हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस खबर पर लिखता है– माणा एवलांच हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश।

और देहरादून स्थित राजभवन में 7 मार्च से दिखेगा रंग– बिरंगे फूलों का संसार– इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है कि वसंतोत्सव की तैयारी पूरी, 7 से 9 मार्च तक 15 मुख्य प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन।